के लिए एजेंसियों का गठन सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का 25% केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है ।

(ग) गत दो वर्षों (1989–90 और 1990–91) के दौरान एल०पी०जी० की 340 डिस्ट्रीब्यूटरशिपें और पेट्रोल/डीजल की 549 खुदरा बिक्री केन्द्रों का आवंटन किया गया था जिसमें से एल०पी०जी० 47 डिस्ट्रीब्यूटरशिपों और 114 खुदरा बिक्री केन्द्रों को अ०जा०/अ०ज०जा० को आवंटित किया गया था अन्य समुदायों के बारे में जानकारी नहीं रखी जाती है ।

Natural Gas in Rajasthan

323. SHRI BHUVNESH CHATURVEDI : Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state :

(a) tha latest position of natural gas reservess found in Rajasthan ; and

(b) the capicity of such reserves and the total amount alljtted to such projects for prodution and research programme ?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI B. SHANKARANAND) : (i) and (b) As on 1-1-1991 OIL and ONGC hive estab-1 lisned in placag is reserves of about 6.68 bllion cubic msres and 1.96 billion cubic ourss respecively.

कच्चे तेल का आयात

324. **श्री राम जेठमलानी :**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में कच्चे तेल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर होने वाला व्यय पिछले कुछ वर्षों से लगातार बढ़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो 1990–91 और 1991–92 के वर्षों के दौरान देश में आयातित कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का कुल मूल्य कितना था ;

(ग) क्या सरकार ने 1992–93 के आगामी वर्ष के दौरान ऐसे उत्पादों के आयात मूल्य में संभावित वृद्धि का कोई आकलन किया है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने आयात व्यय में हो रही वृद्धि को रोकने के लिए घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयास किये हैं, यदि हां, तो सरकार द्वारा हाल के वर्षों में किये गये प्रयासों का ब्यौरा क्या है ;

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) वर्ष 1990–91 के दौरान आयात बिल करीब 10779 करोड़ रुपए का था और वर्ष 1991–92 के लिए इसे 12,000 करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है ;

(ग) वर्ष 1992–93 के लिए आयात बिल वर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विद्यमान मूल्यों और आयात की मात्रा पर निर्भर करेगा ।

(घ) सरकार ने तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की पांच प्रमुख तेल क्षेत्र विकास परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है अर्थात् पश्चिमी अपतट में नीलम मुक्ता और पन्ना क्षेत्रों के विकास की परियोजनायें और बम्बई क्षेत्र के एल–II और एल–III रिजर्वायरों के अतिरिक्त विकास की परियोजनायें वर्तमान रिफाइनरियों का विस्तारण/अवरोध दूर करके और नई ग्रासरूट रिफाइनरियों को स्थापित करके शोधन क्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है ।

अपरिष्कृत तेल का उत्पादन लक्ष्य

325. **श्री रणजीत सिंह :**
डा० जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में